State Governments for taking strict action against corruption and misuse of funds under JRY. Instructions have been issued to the Collectors/Project Officers, DRDAs, during the annual workshops, to deal firmly with cases of misappropriation, embezzlement, corruption etc. With the enactment of Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, the establishment and duration of State Panchayati Raj Institutions (PRIs) have been ensured. The PRIs will also have adequate powers to check any misuse of funds under JRY.

रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर

1514. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1983–84 में एक स्व-रोजगार योजना प्रारंभ की थी ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के नये अवसर पैदा करने के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो योजना के प्रारंभिक वर्ष 1983–84 में इस संबंध में क्या वार्षिक लक्ष्य रखा गया था ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उपलब्धियां क्या रही थीं ; और

(ङ) वर्ष 1993–94 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) प्रारंभिक वर्ष 1983–84 के लिये वार्षिक लक्ष्य 2.50 लाख लाभार्थी निर्धारित किया गया था ।

(घ) वर्ष 1992–93 के लिये निर्धारित लक्ष्य 1.00 लाख लाभार्थी था । 70344 मामलों में ऋण स्वीकृत किये गये जो लक्ष्य का 70.34 प्रतिशत बनता है ।

(ङ) वर्ष 1993–94 के लिये लक्ष्य 1.26 लाख लाभार्थी निर्धारित किया गया है यदि उपलब्धि शत-प्रतिशत होती है तो इसका अर्थ होगा कि वर्ष 1993–94 के दौरान देश के 1.26 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा ।

ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा

1515. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामीण विकास के लिये सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1992–93 के लिये वार्षिक बजट में इन योजनाओं/कार्यक्रमों में से प्रत्येक के कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित राशि में से भिन्न-भिन्न योजनाओं पर वास्तव में अलग-अलग कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आवंटित धनराशि को प्रशासनिक

कार्य-कुशलता की कमी के कारण पूर्णतः प्रयुक्त नहीं किया जा सका है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल)) : (क) और (ख) जी हां, केन्द्र सरकार देश में ग्रामीण विकास के लिये कई कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रही है । कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम ये हैं:-

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,

(2) जवाहर रोजगार योजना, और

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

(ग) और (घ) 1992-93 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिये निधियों का आबंटन तथा उनका उपयोग इस प्रकार है:-

कार्यक्रम	आबंटन (करोड़ रुपये)	उपयोग (करोड़ रुपये में)	उपयोग की प्रतिशतता
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	662.22	705.05	106.50
जवाहर रोजगार योजना	2556.22*	2687.65	105.1.
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	460.00	458.99	99.78

*31-3-93 की स्थिति के अनुसार संशोधित आबंटन 3169.56 करोड़ रुपये था ।

(ङ) और (च) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना में निधियों के उपयोग का प्रतिशत आबंटन से अधिक है । तथापि, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के बारे में निधियों के उपयोग की प्रतिशतता लगभग शत प्रतिशत थी ।

Land use survey of Vidarbha by remote sensing Satellite

1516. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the soil and Land use survey of the 9 Districts of Vidarbha has been completed by the Remote Sensing Setellite; and

(b) if so, by when the results are likely to be available?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTERS OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Yes, Sir.

(b) The soil survey maps on 1:250,000 scale using satellite remote sensing data and extensive ground data have been carried out for all the 9 districts of Vidarbha by National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, Nagpur. These maps provide information on characteristics and their extent in each category. These maps will be printed after obtaining approval of Indian Council of Agricultural Research, Government of India. Besides, Department of